

हॉटलाइन मेंटेनेस करने वाले कर्मियों का भत्ता हुआ दोगुना

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर के निर्देश पर मध्यप्रदेश पांच ट्रांसमिशन कम्पनी (एम.पी.ट्रांसको) में एकस्ट्रा हाईटेंशन लाइनों एवं सब-स्टेशनों का हॉटलाइन पद्धति से बिना शट-डाउन लिये मेंटेनेस जॉब्स/ऑपरेशन करने वाले कर्मियों के भत्ते में दोगुनी बढ़ोतारी की गई है। साथ ही प्रति ऑपरेशन के लिये दिये जाने वाले भत्ते में भी दोगुनी बढ़ि कर दी गई है।

भत्ता अब दोगुना मिलेगा। पहले यह 6 रुपये से 40 रुपये के मध्य था, अब यह 12 रुपये से 80 रुपये तक प्रति जॉब्स/ऑपरेशन के हिस्साब से मिलेगा। हॉटलाइन पद्धति के माध्यम से बिना शट-डाउन लिये एकस्ट्रा हाईटेंशन लाइनों का मेंटेनेस जॉब्स करने के लिये कर्मिकों को सहमति आवश्यक होती है। एम.पी.ट्रांसको द्वारा उन कर्मिकों को बैंगलुरु के केन्द्रीय विद्युत प्राप्तिकरण से प्रशिक्षण लियावाने के बाद ही वह जॉब्स/ऑपरेशन के लिये पात्र होता है। जॉब्स/हॉटलाइन ऑपरेशन अल्पतम जॉब्स भारी होने के कारण कर्मियों को यह भत्ता दिया जाता है। पहले यह सिफर नियमित कर्मियों के लिए लागू था।

भोपाल में एनपीएस कर्मचारियों का प्रदर्शन 1 अप्रैल को

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। नेशनल मूर्खमेंट फारू ओल्ड पैशन स्कॉप के भोपाल जिला इकाई ने आंदोलन की घोषणा की है। नई पेंशन योजना के विरोध में संगठन ने 1 अप्रैल 2025 को विरोध प्रदर्शन का एलान किया है।

कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि पुरुषी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाए। इस दिन सभी एनपीएस कर्मचारी काली पट्टी बांधक अपने कार्यालयों में काम करेंगे। कार्यालयों का विरोध दर्शकरण। साथ ही प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पुरुषी पेंशन योजना की बहाली के लिए जापान से जापौंगे। भोपाल जिले के जिला अध्यक्ष सुप्रसिद्ध प्रसाद पटेल के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

विश्व जल दिवस पर सेंट जोसेफ कोलार में जागरूकता कार्यक्रम

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। सेंट जोसेफ को-एड स्कूल कोलार रोड में आज विश्व जल दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नेशनल केंटर कर (एनसीसी) के समर्थनों परापर्थना सभा के दौरान जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला।

फैक्टेट्रस ने एक प्रभावशाली नाटक के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। नाटक में दिखाया गया कि बढ़ते प्रदूषण से जलसंचय प्रियल रहे हैं। यह स्थिति पृथ्वी के लिए गंभीर खतरा बन रही है। प्रदूषण से पेंड़ों की जड़ें कमज़ोर हो रही हैं। नदियों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कार्यक्रम में पर्यावरण बचाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। इनमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना शामिल है। फैक्टरियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने की आवश्यकता बताई गई। पेट्रोल-डीजल वाहनों के स्थान पर सीएनजी वाहनों के उपयोग पर बल दिया गया।

आंगनवाड़ियों में बर्तन खरीदी में गड़बड़ी

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। आंगनवाड़ियों के बर्तन खरीदी में अपर्याप्त ने हड्डे पार कर दी। स्टील का लालस 162 रुपये, थारी 60 रुपये और चम्मच 38 रुपये में खरीदी गई। रोबा कमिशनर की जांच में शुरूआत में ही गड़बड़ी सामने आ गई। सिंगरीली के जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्वाचित कर दिया गया है। कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल ने इस भ्रात्याचार को लेकर सबाल पूछा था।

महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने बताया कि आदेश अनुसार सामग्री प्रदाय की प्रक्रिया जारी है और भूतान अभी नहीं हुआ है। विधायक ने सावल के लिए बर्तन खेले बाजार से कई गुना अधिक दर पर जैम पोर्टल से खरीदे गए, जिससे सरकार को नुकसान हुआ।

जिले में यह खरीदी जिला कार्यक्रम अधिकारी एक ही फर्म से कर रहे हैं। सिंगरीली में प्रति केंद्र 30 थाली 610 रुपये की, 46500 नग लालस 162 रुपये में, चम्मच 38 रुपये में, 6200 नग

भाजपा विधायक सबनानी ने उठाया मुद्दाःपीएम आवास 6 साल तक लेट, लोग चुका रहे याज

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर के निर्देश पर मध्यप्रदेश पांच ट्रांसमिशन कम्पनी (एम.पी.ट्रांसको) में एकस्ट्रा हाईटेंशन लाइनों एवं सब-स्टेशनों का हॉटलाइन पद्धति से बिना शट-डाउन लिये मेंटेनेस जॉब्स/ऑपरेशन करने वाले कर्मियों के भत्ते में दोगुनी बढ़ोतारी की गई है। साथ ही प्रति ऑपरेशन के लिये एकस्ट्रा हाईटेंशन लाइनों का मेंटेनेस जॉब्स करने के लिये कर्मिकों को सहमति आवश्यक होती है। एम.पी.ट्रांसको द्वारा उन कर्मिकों को बैंगलुरु के केन्द्रीय विद्युत प्राप्तिकरण से प्रशिक्षण लियावाने के बाद ही वह जॉब्स/ऑपरेशन के लिये पात्र होता है। जॉब्स/हॉटलाइन ऑपरेशन अल्पतम जॉब्स भारी होने के कारण कर्मियों को यह भत्ता दिया जाता है। पहले यह सिफर नियमित कर्मियों के लिए लागू था।

ऊर्जा मंत्री श्री तोमर को पहल पर मध्यप्रदेश था, अब यह 12 रुपये से 80 रुपये तक प्रति जॉब्स/ऑपरेशन के हिस्साब से मिलेगा। हॉटलाइन पद्धति के माध्यम से बिना शट-डाउन लिये मेंटेनेस जॉब्स करने के लिये कर्मिकों को सहमति आवश्यक होती है। एम.पी.ट्रांसको द्वारा उन कर्मिकों को बैंगलुरु के केन्द्रीय विद्युत प्राप्तिकरण से प्रशिक्षण लियावाने के बाद ही वह जॉब्स/हॉटलाइन ऑपरेशन के लिये पात्र होता है।

जिन लोगों ने इसमें फलैट बुक किए हैं, उन्हें बैंक लोन की किस्त और ब्याज भरना पड़ रहा है और आवास भी नहीं मिले हैं। नगर निगम भोपाल निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रख रहा है। बाद से अब तक कुल 342 लोगों की राशि जमा कर दी है। जबकि में भी उदय प्रताप सिंह ने कहा कि यह गंगा नगर आवास योजना के लिए जापान कर्मियों को भी बोर्ड कर दिया है।

इसके लिए गुजरात की कंपनी एमपी



दिया और इन्हें 18 महीने में पूरा काम करना है। मंत्री ने कहा कि 72 आवासों का निर्माण पूरा हो गया है और बाकी का काम दिसंबर 2025 तक करेंगे। ठेकेदारों को 6 बार समय भी दिया गया। इसके बाद भी काम नहीं हुआ तो उनके एपीएमेट को टर्मिनेट कर दिया गया है। नई कंपनी एसआरएस इन्फा को अक्टूबर 2023 में काम

मार्च को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंधार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने स्पीकर को जापान सोपाकर भाजपा उन्हें भी क्षेत्र के विकास के लिए ड्वलपमेंट फंड के 15-15 करोड़ रुपये की मांग की। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि मप्र में भाजपा के विधायकों को उनके क्षेत्रों के विकास के लिए हर साल सोएम 15-15 करोड़ रुपये दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस विधायकों को उनके क्षेत्रों के विकास के लिए रुपये नहीं दिलाते हैं। अब तक कलेक्टर ने सूची नहीं भेजी है। उन्होंने गंगा नगर प्रोजेक्ट के लिए दोस्रे दोस्रे एक रुपये दिलाते हैं। इनमें 12 नंबर बस स्टॉप, बाग मुगालिया एक्सटेंशन, श्याम नगर, कोकता, हिनोतिया, कलखेड़ा, मालीखेड़ी, गरसलाखेड़ा आदि की स्थिति भी ऐसी ही। उन्होंने कहा कि लोग केवल निर्माण में हो रही देरी से ही परेशान नहीं है। इसके अलावा उन्हें रजस्ट्री में 25 फीसदी की छूट नहीं दी जा रही है। अब तक तकलीकरने के लिए गंगा नगर में ऐसे 13 और प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इनमें 12 नंबर बस स्टॉप, बाग मुगालिया एक्सटेंशन, श्याम नगर, कोकता, हिनोतिया, कलखेड़ा, मालीखेड़ी, गरसलाखेड़ा आदि की स्थिति भी ऐसी ही।

त्योहार का सामाजिक एकजुटता में महत्वपूर्ण योगदान : राज्यमंत्री गौर

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। पिछड़ा वर्ष एवं अल्पसंख्यक कलायण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभारी) श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा कि त्योहार का सामाजिक एकजुटता में महत्वपूर्ण योगदान है। परंपरा, त्योहार के आयोजन से हमारी संस्कृति समृद्ध हो रही है। ये सामाजिक एकता को भी मजबूत कर रहे हैं। राज्यमंत्री श्रीमती गौर शनिवार को भानुपुर भोपाल में ट्रेलर विकास एवं व्यापारी संघ द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह के संबोधित कर रही थी।

राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि समाजों के लिए यहां उपस्थिति का सनातनी परंपरा अनुसार त्योहार समाज को एकजुट रखने का काम कर रहे हैं। त्योहारों का उल्लास, उत्साह हमारे प्रमुख और जीवन को आनंद से भर देता है। हमारे त्योहार जीवन में तनाव को दूर कर आनंद की अनुभूति कराते हैं।

राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि समाजों के माध्यम से सनातन संस्कृति का समाजन करने के लिए यहां सभी व्यापारी बंधुओं को होली और रंग चंचली के पावन पर्व को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं। होली मिलन समारोह में स्थानीय पार्श्व श्री विकास पटेल, श्री राजौर, श्री नीलेश गौर, श्री प्रकाश पटेल, श्री विनोद साहू, श्री प्रमोद गुप्ता, श्री मुकेश यादव सहित व्यापारी बंधु मौजूद रहे।

कर्मचारी संघ ने मुख्य सचिव से की मुलाकात

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। मध्य प्रदेश क

बस और सफारी कार की टक्कर, तीन लोग घायल, भैसरहा पेट्रोल पंप के पास हादसा

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। रीवा-शहडोल मार्ग पर भैसरहा पेट्रोल पंप के पास रविवार दोपहर 3.30 बजे बस और सफारी गाड़ी में आपने-सामने की टक्कर हो गई।

हादसे के तहाँ जब सफारी गाड़ी पेट्रोल भरवाने के बाद पेट्रोल पंप से बाहर निकल रही थी। तेज रफ्तार में आ रही बस सफारी से टक्कर गई। टक्कर में बस का आगता द्विस्तरा और सफारी गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।

सफारी चालक रमेश जयसवाल को सिर में छोट आई है। उन्हें रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस में सवार महेंद्र तिवारी और हरेंद्र कुश्वाह भी घायल हुए हैं। अन्य यात्रियों को मामूली चोटें



गांजा बेचते एक आरोपी गिरफ्तार पुलिस ने 650 ग्राम नशीला पदार्थ जब्त किया

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। सीधी जिले के कुसमी थाना पुलिस ने मेडो गांव में रविवार को एक व्यक्ति को गाजा बेचते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 650 ग्राम गांजा बारामद हुआ है। इसकी कीमत बाजार में 11 हजार रुपए से अधिक है। मुख्यमंत्री से मिली सूचना के बाद कुसमी थाना प्रभारी भूपेश कुमार बैठे ने कार्रवाई की।

पुलिस अधिकारी के निर्देश पर विशेष इस आधार पर आगे की जांच की जा रही है। टीम ने मेडो गांव नदी पर प्रकाश सिंह, रामेश्वर सिंह, कन्दलेश प्रजापति समेत आरक्षक दिव्येश सिंह, दिनकर द्विवेदी, पंकज सिंह और शिवराम वैश्य शामिल थे। एकट के तहत मामला दर्ज किया है।

60 वर्षीय देवचरण अपने घर से ही गांजा बेच रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एकट के तहत मामला दर्ज किया है।

क्षेत्र में लगातार हो रही छापेमारी से नशा तस्करों में हड्डकप मचा हुआ है।

खूंटा उखाड़ने के शक में दंपती को लाठी-डंडों से पीटा, तीन लोगों पर केस दर्ज, सीधी जिले के माटा गांव की घटना

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। सीधी जिले के माटा गांव में केवट दंती पर दंडों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। घटना का वीडियो रविवार को सामने आया। पीड़ित परिवार ने मज़ाली थाने में शिकायत की है। पुलिस ने धारा 155 के तहत मामूली अपराध दर्ज किया है। पीड़ित बबूल केवट ने बाताया कि भीमसंग मिश्र, पृष्ठ मिश्र और मोहित मिश्र ने उन्हें और रामकृष्णपाल केवट को लाठी-डंडों से पीटा। आरोपियों ने पुरानी रीजेंस और खुंटा उखाड़ने के शक में यह हमला किया।

पीड़ित परिवार का कहना है कि इससे पहले भी दंडों ने उनके साथ मारपीट की थी। पुलिस के सख्त कार्रवाई नहीं करने से आरोपी बेंचोंप हैं। थाना प्रभारी से शिकायत के बाद भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में युवाओं के पंजीयन की अतिम तिथि 31 मार्च

सीधी। प्राचीय औंगोलिक प्रशिक्षण संस्था ने जाकरी देकर बताया है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) का देवेंश युवाओं को भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अंतर्गत प्रदान कर रोजानाप्रक बनाना है। जिससे युवाओं को वास्तविक कार्यानुभव प्राप्त हो सके और अंग्रेजी को लाठी-डंडों से भालौने के बाद भी बढ़ावा दिया जाए। योजना में 21 वर्ष से 24 वर्ष आगे के युवा नियन्त्री शैक्षणिक योग्यता 10वीं, 12वीं, आईआईआई, पॉलिटेक्निक या प्रैक्टिसिटेक किये हैं और वे किसी अप्रैटेस या पॉलिकालिक रोजगार में न हों। ऐसे युवा प्रजीवन का सफर तुम्हारों को इंटर्नशिप की अवधि में 5000 रुपये प्रति माह स्टायर्ड और एकलाइन 6000 रुपये प्रति माह दिया जायेगा।

मीडिया ऑडीटर, शहडोल (निप्र)। शहडोल में रविवार को पुलिस पर पथराव के चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सराफा व्यापारियों की तलाश में बुद्धरुप हुए गोलीकांड में इस्तेमाल किया गया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि गोलीकांड में इस्तेमाल किया गया था। वाहन बहाने देखा गया है। पथराव में महिला कार्नेल तीव्र तीव्र तीव्र घायल हुए थे।

मालती में गिरफ्तार आरोपी

फिरोज अली जाफरी, खानू अली,

मनोहर अली और सादर अली शामिल हैं। पुलिस ने कुल 18 लोगों के दिलाक नामजद एक आईआईआर दर्ज की है। थाना प्रभारी संजय जायसवाल के अनुसार, शेष फरार आरोपियों की तलाश के लिए टीमें विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं।

गोरतलब है कि मूल आरोपी

यूसूफ और तीहीद कई यात्रों में बालौने के बालौने में बालौत हैं। मध्य प्रदेश के मामलों में बालौत हैं।

मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की पुलिस भी इन दोनों की तलाश कर रही है।

यह क्षेत्र सान घायल अभयारण्य से सटा हुआ है। फिर भी यहां लालार अवैध खनन की शिकायत मिल रही थीं।

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। सिंगरौली जिले के चितरी क्षेत्र में सात नदी से अवैध रेत खनन का मामला सामने आया है। नौदिला चौकी पुलिस ने रेत से भरे एक ट्रैक्टर-टॉली को जल लिया है। सात नदी में रेत निकाली और खनन पर प्राप्ति की गयी है। यह क्षेत्र सान घायल अभयारण्य से सटा हुआ है। फिर भी यहां लालार अवैध खनन की शिकायत मिल रही है।

मीडिया ऑडीटर, भैसरहा

पेट्रोल पंप के पास नदी की ओर से एक ट्रैक्टर लेकर आ रहा था। सूचना मिलते ही

इलाके में आधा दर्जन से ज्यादा पकड़े मानक तोड़े गए थे। ये मकान लेवे समय से सरकारी जमीन पर बने हुए थे। पहली कार्रवाई के बाद इस दर्जन की ओर भारी मालौली लीपक सिंह बघेला ने बताया कि दोनों पकड़े में बिवाद हुआ है। प्रश्नासन से न्याय की मांग: पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें लगातार धमाकियां दी जा रही हैं। ये खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने प्रश्नासन से जर्द जर्द समर्थन प्राप्त है। इसी कारण पुलिस ने जर्द जर्द आरोपियों की गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई की मांग की है। वही इस घटना के बाद गांव में भी भय का मालौल बना हुआ है।

प्रश्नासन की ओर से न्याय की मांग: पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की जांच की जा रही है।

प्रश्नासन की ओर से न्याय की मांग: पीड़ित परिवार ने मामले की जांच की जा रही है।

बसों और लोडिंग गाड़ियों की फिटनेस जांच सिंगरौली आरटीओ के उड़दस्ता ने देखे खिड़की, दरवाजे और पैनिक बटन, नियमों के उल्लंघन पर वसूला जुर्माना



मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। सिंगरौली जिले में सड़क हादसों को रोकने के लिए आरटीओ विभाग का उड़दस्ता कंसर्ट गेट से खनहना तक लगातार जांच कर रही है। टीम मुख्य रूप से यात्री बसों में आपातकालीन खिड़की, दरवाजे, पैनिक बटन के बोर्ड और टायर की नियमित जांच, क्षमता से अधिक सवारी न बैठाना, नियमानुसार बिल्डिंग के बोर्ड और टायर की नियमित जांच कर रही है। बाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बाहन का नियमित रखरखाव करें और सभी जारी रहें। बाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बाहन का नियमित रखरखाव करें और सभी जारी रहें।

चेक पॉडिंग प्रभारी अनिमेष जैन के नेतृत्व में उड़दस्ता टीम कसर गेट से खनहना तक लगातार जांच कर रही है। अनिमेष जैन ने बताया कि बस चालकों को दिर्देंश दिए जा रहे हैं। इनमें बस के बोर्ड और टायर की नियमित जांच, क्षमता से अधिक सवारी न बैठाना, नियमानुसार बिल्डिंग के बोर्ड और टायर की नियमित जांच कर रही है। बाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बाहन का नियमित रखरखाव करें और सभी जारी रहें।

6 पिकअप से 23 मवेशी मिले दो पिकअप पलटे, अमलाई पुलिस ने की कार्रवाई

मीडिया ऑडीटर, शहडोल (निप्र)। शहडोल के अमलाई थाना क्षेत्र में पुलिस ने मवेशी तस्करी का खुलासा हुआ है। रामपुर गिरवा हार्डिंग पर पुलिस की नाकबंदी के दौरान 6 पिकअप विभिन्न धाराओं में मालौल दर्ज किया है। एसपी रामजी श्रीवास्तव के नियन्त्रण में फरार के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले जैतपुरी में बाहन के बोर्ड और टायर की नियमित जांच कर रही थी। इस बाहन के बोर्ड और टायर की नियमित जांच करने के बाद अधिकारियों से न्याय की गुहार उल्लग है, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके और भावित्य में इस तरह की घटना की घटनाका बोर्ड और टायर की नहीं है। यह बाहन तीन दिन पुरानी था। आपातकालीन धाराएं भी जारी रही हैं। प्रभारी मध्योली लीपक सिंह बघेला ने बताया कि दोनों पकड़े में बिवाद हुआ है।

पुलिस की

विद्या

बंगाल की सभी सीटों पर संगठन को मजबूत करेगी कांग्रेस

कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक कर उन्हें राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों पर संगठन को मजबूत करने का टास्क दे दिया है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पार्टी के नेताओं को पश्चिम बंगाल में जनाधार और संगठन को मजबूत करने की सलाह दी है।

दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय %इंदिरा भवन% में
बुधवार को खरगे की अध्यक्षता और राहुल गांधी
एवं केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में हुई बैठक में
पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर,
पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शुभांकर
सरकार, वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी और दीपा
दासमुंशी सहित बंगाल कांग्रेस के कई अन्य बड़े नेता
शामिल हुए।

पश्चिम बंगाल में राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों पर संगठन को मजबूत बनाने की कांग्रेस की कवायद के साथ ही यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा ? क्या कांग्रेस के मजबूत होने का खामियाजा पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उठाना पड़ेगा ? या फिर कांग्रेस की मजबूती से भाजपा को नुकसान उठाना पड़ेगा, जो ममता बनर्जी विरोधी मतों के सहारे राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति पर काम कर रही है।

इसके लिए हमें वर्ष 2016 और वर्ष 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करना पड़ेगा। वर्ष 2016 में पश्चिम बंगाल में राज्य की सभी 294 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी ने 45.6 प्रतिशत वोट हासिल कर राज्य की 211 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वर्ष 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को वोट भी ज्यादा मिले और सीटों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई। 2021 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में 48.5 प्रतिशत वोट हासिल कर टीएमसी ने 213 सीटों पर कब्जा जमाया था। बीजेपी के प्रदर्शन की बात करें तो 2016 में राज्य की 291 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद पार्टी के खाते में सिर्फ 3 सीटें ही आ पाई थीं और मत भी 10.3 प्रतिशत ही मिल पाया था। वहीं उस चुनाव में लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर लड़ी कांग्रेस ने 12.4 प्रतिशत मत के साथ 44 सीटें जीती थीं। 2021 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन सबसे ज्यादा शर्मनाक रहा। जबकि भाजपा के शानदार प्रदर्शन ने राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया। पिछले चुनाव में कांग्रेस का मत प्रतिशत 12.4 प्रतिशत से घटकर महज 3 प्रतिशत रह गया और पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं आ पाई।

मुस्लिम आरक्षण के मोह नहीं छोड़ पा रही कांग्रेस पार्टी

पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कर्नाटक सरकार द्वारा मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव राहुल गांधी के पूर्ण संरक्षण में पारित किया गया है। हम यह पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता पर निशाना साधते हुए प्रसाद ने कहा कि कर्नाटक सरकार का कदम राहुल गांधी की मानसिकता को दर्शाता है। ऐसा नहीं है कि कर्नाटक के जरिए देशभर के मुसलमानों के प्रति मोहब्बत दर्शने का कांग्रेस का यह पहला मौका है, इससे पहले भी कर्नाटक में मुस्लिमों के आरक्षण को लेकर विवाद रहा है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने आरक्षण का लाभ देने के लिए मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग की लिस्ट में शामिल किया था। सरकार ने मुसलमानों को ओबीसी लिस्ट में जगह दी। हालांकि, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार के इस फैसले की आलोचना की थी। आयोग ने कहा था कि इस फैसले ने सामाजिक न्याय के सिद्धांत को कमज़ोर कर दिया है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक, कर्नाटक राज्य में मुस्लिम की जनसंख्या 12.32 फीसदी है और उसे राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा हासिल है। मध्य प्रदेश की चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस को ओबीसी समुदाय का सबसे बड़ा दुश्मन करार देते हुए कहा था कि एक बार फिर कांग्रेस ने पिछले दरवाजे से ओबीसी के साथ सभी मुस्लिम जातियों को शामिल करके कर्नाटक में धार्मिक आधार पर आरक्षण दिया है। विवाद बड़ा तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि यह दावा करना कि कांग्रेस ने पिछड़े वर्गों से मुसलमानों को आरक्षण टांसफर कर दिया, एक सरासर झूठ है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या पूर्व प्रधानमंत्री



देवेगौड़ा अभी भी मुसलमानों के लिए कोटा के अपने समर्थन पर कायम हैं या नरेंद्र मोदी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है।
गैरतलब है कि यह आरक्षण पहली बार 1995

गारतलब ह कि यह आरक्षण पहला बार 1995 में एचडी देवगौड़ा की जनता दल ने कर्नाटक में लागू किया था। दिलचस्प बात यह है कि देवगौड़ा की जद (एस) अब बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनराजिक गठबंधन (एनडीए) की सहयोगी है। कर्नाटक सरकार के 14 फरवरी, 1995 के एक आदेश में जिक्र किया गया जिसमें बताया गया कि यह निर्णय चिन्नप्पा रेड्डी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है और आरक्षण को 50

आखिर कब समझेंगे अपनी जिमेदारी ?

समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सिलसिलेवार ढंग से जो संवैधानिक झामा रचाया जा रहा या चल रहा है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारी संसद जिमेदार है, योंकि जनहित में प्रभावशाली कानून बनाने का जिमा उसी के ऊपर है। यदि उसने इस मामले में अबतक किसी तरह की कोई लापरवाही बरती है तो यह जन-बहस का मुद्दा है। इसलिए कुछ सुलगता हुआ सवाल यहां पर प्रासारिक है! लेकिन जब हम संसद की बात करते हैं तो इसकी सीधी जिमेदारी सापक्ष और विपक्ष के जनप्रतिनिधियों और उनके समूह की होती है। योंकि सा की अदलाबदली प्रायः इन्हीं के बीच होती रहती है। संसद के अलावा, हमारी सिविल सोसाइटी, मीडिया मठाधीश, अधिवक्तागण, शिक्षाविद, प्रबुद्ध कारोबारी तबका एवं विभिन्न प्रकार के लोकतांत्रिक दबाव समूह भी इस स्थिति के लिए सामूहिक रूप से जिमेदार हैं, योंकि भले ही इनके पास कोई संवैधानिक शक्ति नहीं है या फिर अलग-अलग प्रकार की कानूनी सहूलियत प्राप्त है, लेकिन जनमत निर्माण में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती आई है।

समाजपालिका भी बहुत ताकतवर होकर उभरी है और सत्ता परिवर्तन में मुख्य भूमिका निभा रही है। हालांकि, इसके संकीर्ण स्रोत से भी समाज दिग्ध्रमित हुआ है।

आमतौर पर राजतंत्रीय सोच और सामंती विचारों से हमारा मौजूदा लोकतंत्र भी संक्रमित हो चुका है। तभी तो भूमि संपदा, मौद्रिक संपदा और स्वर्ण संपदा बनाने की होड़ हमारे माननीयों में मची रहती है। वहीं जो ज्ञान संपदा के धर्नी हैं, वे भी भूमि संपदा, मौद्रिक संपदा और स्वर्ण संपदा बनाने की होड़ में शामिल हो चुके हैं। अफसोस की बात यह है कि हमारा लोकतंत्र और सविधान ही इनकी अवैध और अकृत कमाई का हथकंडा बन चुका है और उच्चपदस्थ लोग इनके खिलाफ एकजूट नहीं हो रहे हैं।

यही वजह है कि जनता दिन-ब-दिन गरीब और उसके शासक लगातार अमीर होते जा रहे हैं। इनके अवैध धन से कहीं आतंकवादी, तो कहीं नक्सली व उग्रवादी फलपूल रहे हैं। भ्रष्टचार, तस्करी, तबादला उद्योग, जबन्य हिंसा-प्रतिहिंसा आदि मानवता विरोधी नीतियों या कार्यों पर निर्णायक चेक एंड बैलेंस का विगत 8 दशकों में भी नहीं बनना इस पूरी व्यवस्था के लिए कलंक की बात है। आखिर अनवरत साप्रदायिक दंगों और राजकोषीय लूट के लिए हमारी संसद नहीं तो कौन जिम्मेदार है, यक्ष प्रश्न है।

कम्पनी, फर्म, ट्रस्ट, एनजीओ आदि को अलग इकाई मानना और उनके दिवालिया व विफल होने पर उनके संचालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई न होना, उनकी या उनसे लाभान्वित लोगों की अन्य सम्पत्तियों तक प्रशासनिक अंच का नहीं पहुंचना हमारी नीतिगत विफलता नहीं तो क्या है? आज भू-सम्पदाओं में जो धोखाधड़ी मची हुई है, मौद्रिक क्षेत्र में डिजिटल धोखाधड़ी लगातार बढ़ रही है, इसके लिए प्रशासनिक जवाबदेही कौन सुनिश्चित करेगा।

अनुभव बताता है कि पुलिसिया भ्रष्टाचार, तहसील कदाचार, न्यायिक जुल्म व लेटलोफी, प्रशासनिक पक्षपात, सियासी अनैतिकता से समूचा समाज भयाक्रांत और परेशान है, लेकिन हमारे माननीयों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। या वैसा कोई सजाग व्यक्ति या समूह भी नहीं है जो इन लोकतांत्रिक महावीरों को उनकी मौलिक शक्ति का एहसास दिलाए।

सवाल किसी जज की कोठी में भारी मात्रा में नोटों के मिलने का नहीं है और न ही उसके खिलाफ लीपापोती वाली प्रक्रिया शुरू करने का है, बल्कि सुलगाता हुआ सवाल यह है कि व्यवस्था के ऐसे जिम्मेदार तत्वों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने में हमारी संवैधानिक व्यवस्था कितनी असहाय प्रतीत होती आई है और आज तक उसका सार्थक और सकारात्मक हल नहीं ढूँढ़ा जा सका है। आपने देखा सुना होगा कि देश को लूटने वाले विदेशों में बस रहे हैं। ऐसे लोग हमारी कानूनी खामियों का फायदा उठाकर विदेशों में मौज कर रहे हैं, क्योंकि उनको परोक्ष सियासी शह व सहूलियत दोनों प्राप्त है। ऐसे में यक्ष प्रश्न यह है कि यदि मौजूदा लोकतांत्रिक व संवैधानिक व्यवस्था जनता की सुख-शांति-समृद्धि सुनिश्चित नहीं कर सकती हैं तो फिर उसके होने या न होने का क्या मतलब रह जाता है। इस नजरिए से आधुनिक लोकतंत्र भी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और पूँजीपतियों के नेतृत्व वाली नई विश्व व्यवस्था आकार ले रही है, जिससे आमलोगों की त्रासदी और बढ़ेगी।

न्यायपालिका की है, जहां वकीलों की दलील के आधार पर
किसी अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। खास बात यह कि
हमारी नौकरशाही के प्रशासनिक विवेक और न्यायपालिका के
न्यायिक विवेक पर भी कोई सवाल उसी तरह से नहीं उठाया जा
सकता है, जिस तरह से विधायिका के विधायी व प्रशासनिक
विवेक और मीडिया के संपादकीय विवेक को मान्यता एवं
संरक्षण प्राप्त है।

दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि समाज का यह जागरूक तबका और उनका जेबी संगठन राजनीतिक रूप से दलित-महादलित, ओबीसी-एमबीसी, सर्वण-गरीब सर्वण, अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक, आदिवासी-आर्य, अकलियत-पसमांदा, भाषा-क्षेत्र, अमीर-गरीब आदि विभिन्न गुटों में बंटा हुआ है, जो अभिजात्य वर्गीय सोच की हिफाजत का टूल्स बना दिया गया है।

वहाँ, संसद द्वारा सही कानून बनवाने और बनाए हुए कानूनों को लागू करवाने में नौकरशाही की बड़ी भूमिका रहती है। जबकि इन कानूनों की व्यायसमत तथा समीक्षा करने और मतभेद या विवाद नहीं प्रियंका में अंतिम चर्चाएँ देते नहीं चिनाएँगी

किसानों को लेकर कांग्रेस और 'आप' के बीच मतभेद उभरा

पंजाब पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारी किसानों पर की गई कार्रवाई के मद्देनजर प्रमुख 'ईडिया' ब्लॉक पार्टियों कांग्रेस और 'आप' के बीच संबंधों में मतभेद बढ़ गए हैं जिसमें कांग्रेस ने 'आप' के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के साथ-साथ भाजपा शासित केंद्र को भी कठघरे में खड़ा करने की पूरी कोशिश की है। सरकान सिंह पंधरे और जगजीत सिंह डल्लेवाल सहित कई किसान नेताओं को केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक से लौटते समय मोहाली में हिरासत में लिया गया। पंजाब पुलिस ने शंभू और खनौरी बार्डर स्थलों से किसानों को हटाया जो एक साल से अधिक समय से अवरुद्ध थे। कांग्रेस और संयुक्त किसान मोर्चा 'एस.के.एम.' ने गुरुवार को आरोप लगाया कि 'आप' और भाजपा ने कई कृषि नेताओं को हिरासत में लेने के बाद किसानों के खिलाफ हाथ मिला लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे ने एक्स पर लिखा, "ऐसा लगता है कि देश के अन्नदाताओं के खिलाफ दो किसान विरोधी पार्टियों ने हाथ मिला लिया है।"

का दौरा करेंगे, जो 2014 में पटभार ग्रहण करने के बाद उनका पहला दौरा होगा। अपने दौरे के दौरान, मोदी आर.एस.एस. समर्थित संस्थान माधव नेत्रालय नेत्र संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र में एक विस्तार परियोजना की आधारशिला रखेंगे। दूसरी ओर, मोदी और संघ नेताओं के बीच बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा को जल्द ही एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है जो इस साल शुरू होने वाले अगले दौर के राज्य चुनावों में पार्टी का नेतृत्व करेगा। आम चुनाव के बाद से भाजपा और आर.एस.एस. के बीच संबंध तनावपूर्ण हैं, जहां मोदी के नारे, ‘अबकी बार चार सौ पार’ को अति आत्मविश्वास के रूप में देखा गया था। भाजपा बहुमत से चुक गई। तब से, संबंधों को सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में चुनावों से पहले भाजपा ने आर.एस.एस. के साथ कई बैठकें कीं, जहां समन्वित प्रयासों ने जीत में योगदान दिया। हाल के दिनों में, पी.एम. ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रशंसा की है, राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता और इसके स्वयंसेवकों के समर्पण की सराहना की है। सूत्रों के अनुसार, मोदी की टिप्पणी उनकी पसंद के भाजपा अध्यक्ष के लिए समर्थन हासिल करने का संकेत हो सकती है।

गरमा रहा है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस महीने के अंत में बिहार में एन.डी.ए. नेताओं से मिलने आ सकते हैं। इस बैठक में इस साल अन्धबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति तैयार करने पर जोर दिया जा सकता है। शाह चुनिंदा तौर पर राज्य के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। अमित शाह का यह दौरा इस बात के मद्देनजर महत्वपूर्ण है कि उन्होंने हाल ही में घोषणा की थी कि वह बिहार में डेरा डालेंगे और चुनाव अभियान की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करेंगे। शशि थरूर द्वारा पी.एम. मोदी की प्रशंसा = कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा प्रधानमंत्री नंदेंद्र मोदी की सराहना ने वास्तव में कांग्रेस और राहुल गांधी को एक शर्मनाक स्थिति में डाल दिया है क्योंकि भाजपा ने कांग्रेस और उसके नेतृत्व पर निशाना साधा है।

मंगलवार को नई दिल्ली में यासीना डायलॉग में 'शांति कायम करना, पीछे मुड़कर देखना और आगे देखना' शीर्षक से एक संवादात्मक सत्र के दौरान, थर्सर ने कहा, "मैं अभी भी अपने चेहरे से अंडे पौँछ रहा हूं व्योर्किंग मैं संसदीय बहस में एकमात्र व्यक्ति हूं जिसने वास्तव में फरवरी 2022 में उस समय अपनी दिल्ली रसी अपेक्षा तक रखी।"

